कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत अपंजीकृत कम्पनियां

7324. **श्री राजनाथ सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसी कितनी निजी कम्पनियां हैं जिनका पंजीकरण कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत नहीं कराया गया है और इस संबंध में कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली में ऐसी कई निजी कम्पनियां हैं जिनके मालिकों द्वारा एक ही कम्पनी के नाम से अन्य अलग-अलग कम्पनियां खोली गई हैं और क्या मैसर्स डिजाइन, मैसर्स इनड्योर, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली भी इन कम्पनियों में से है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने इन कम्पनियों के मालिकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) कम्पनी कार्य विभाग के पास ऐसी कम्पनियों के बारे में कोई सूचना नहीं है तो कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत नहीं हैं। इसलिए, ऐसी कम्पनियों के स्वामियों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

मैसर्स डिजाइन और मैसर्स इनड्योर नाम से कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कम्पनियों के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उपलब्ध सूचना के अनुसार इस प्रकार की कोई कम्पनियां नहीं हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के पास लंबित आर्डर

7325. **श्री आस मोहम्मद:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के पास बड़ी संख्या में आर्डर लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं कि यह एकक आवश्यक कार्यपूंजी की कमी का सामना न करे;

(घ) क्या सरकार देश के पूर्वी भागों में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के इंजीनियरिंग एककों की पुनरुत्थान योजनाओं को तैयार करने हेतु निगम के पास उपलब्ध विशेषज्ञता का उपयोग करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) दिनांक 1.5.95 की स्थिति के अनुसार हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड की क्रयादेश स्थिति 483 करोड़ रुपए थी। क्षेत्रवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

(करोड़ रुपए में)

इस्पात	312
खनन	82
रक्षा	9
रेलवे	34
अन्य	46
	483

(ग) सरकार अपनी बजटीय सीमाओं के अन्दर कंपनी को वित्तीय सहायता देती है, जिसमें कंपनी को कार्यशील पूंजी संबंधी सहायता देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को स्थायी गारंटी शामिल है।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास केन्द्र

7326. **श्री सुरेश पचौरी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं ने केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करने संबंधी नीति